



भारत की बदलती खाद्य प्रणालियाँ

प्रलिस के लयः

NFHS-5, हरतऱ क्रांतऱ, खाद्य एवं कृषऱ संगठन, संयुक्त राषट्र

मेन्स के लयः

खाद्य प्रणालयऱ के स्थरऱता और भवषऱ कऱ चुनौतयऱ

चरचा में कयऱ?

जलवायु परवरऱतन के कारण आने वाले वरषऱ में खाद्य प्रणालयऱ के स्थरऱता महत्त्वपूरण होने जा रही है ।

- भारत को अपनी खाद्य प्रणालयऱ में भी परवरऱतन करना होगा, जन्ऱहें उच्च कृषऱआय और पोषण सुरक्षा के लयऱ समावेशऱ और टकरऱऊ होना चाहयऱ ।
- इससे पहले खाद्य प्रणालऱ पर [संयुक्त राषट्र](#) की रऱऱरऱट में बताया गया था कऱ वरऱतमान खाद्य प्रणालयऱ शक्तऱ असंतुलन और असमानता के कारण अत्यधकऱ प्रभावतऱ हैं और अधकऱंश महलऱओं के पक्ष में नहीं हैं ।

प्रमुख बढऱ

- **खाद्य प्रणालऱ:**
 - [खाद्य एवं कृषऱसंगठन](#) (FAO) के अनुसार, खाद्य प्रणालयऱ में कारकऱ के पूरऱ शृंखला शामिल है:
 - कृषऱ, वानकऱ या मत्स्य पालन से प्राप्त खाद्य उत्पादऱ के उत्पादन, एकतऱरीकरण, प्रसंसकरण, वतरण, खपत, नऱऱटान और वऱापकता आरथकऱ, सामाजकऱ एवं प्राकृतकऱ वातावरण के कुछ हसऱसऱ में अंतरनहऱतऱ है ।
- **भारतऱय खाद्य प्रणालयऱ के सममुख उपस्थतऱ वभऱनऱन चुनौतयऱ:**
 - **हरतऱ क्रांतऱ का प्रभाव:**
 - यद्यपऱ [हरतऱ क्रांतऱ](#) के कारण देश के कृषऱ वकऱस में महत्त्वपूरण प्रगतऱ हुई है, लेकनऱ इसने जल-जमाव, मडऱटी का कटाव, भू-जल कऱ कमी और कृषऱ कऱ अस्थरऱता जैसी समस्याओं को भी जन्म दयऱ है ।
 - **वरऱतमान नीतयऱ:**
 - वरऱतमान नीतयऱ अभी भी 1960 के दशक कऱ घाटे कऱ मानसकऱता पर आधारतऱ हैं । खरऱद, सबसडऱई और जल नीतयऱ चावल और गेहूँ के पक्ष में हैं ।
 - तीन फसलऱ (चावल, गेहूँ और गन्ना) कऱ सचऱई में 75 से 80% पानी का प्रयोग होता है ।
 - **कुपोषण:**
 - [NFHS-5](#) से पता चलता है कऱ वरऱष 2019-20 में भी कई राज्यऱ में कुपोषण में कमी नहीं आई है । इसऱ तरह मोटापा भी बढऱ रहा है ।
 - ग्रामीण भारत के लयऱ EAT-Lancet आहार संबंधऱ सफऱरऱशऱ के आधार पर प्रतऱ वऱयक्तऱ लागत प्रतऱदऱनऱ 3 अमेरकऱ डऱलर और 5 अमेरकऱ डऱलर के बीच है । इसके वऱऱरऱत वास्तवकऱ आहार लागत प्रतऱ वऱयक्तऱ प्रतऱदऱनऱ लगभग 1 अमेरकऱ डऱलर है ।
- **भारत कऱ खाद्य प्रणालयऱ को बदलने के लयऱ आवश्यक कदम:**
 - **फसल वऱवऱधऱकरण:**
 - पानी के अधकऱ समान वतरण, टकरऱऊ और जलवायु-लघऱली कृषऱ हेतु बाजरा, दलहन, तलऱहन, बागवानी के लयऱ फसल पैटर्न के वऱवऱधऱकरण कऱ आवश्यकता है ।
 - **कृषऱ कषेतर में संस्थागत परवरऱतन:**
 - [कसऱन उत्पादक संगठनऱ](#) (FPO) को छोटे भूमऱधारकऱ को इनपुट और आउटपुट के बेहतर मूल्य कऱ प्राप्तऱ में मदद करनी चाहयऱ ।
 - [ई-चऱपाल](#) जैसी पहल छोटे कसऱनऱ को लाभानवतऱ करने वाली प्रऱदयऱगकऱ कऱ एक उदाहरण है ।
 - महलऱ सशकऱतीकरण वऱशऱष रूप से आय और पोषण बढऱने के लयऱ महत्त्वपूरण है ।
 - केरल में महलऱ सहकारऱ समतऱयऱ और [कुदुमबशऱरऱ](#) जैसे समूह इसमें मददगार हऱंगे ।
 - **सतत खाद्य प्रणालऱ:**

- अनुमान बताते हैं कि खाद्य क्षेत्र विश्व के लगभग 30% [ग्रीनहाउस गैसों](#) का उत्सर्जन करता है।
- उत्पादन, मूल्य शृंखला और खपत में स्थिरता हासिल करनी होगी।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा:**
 - [कोवडि-19](#) महामारी ने भारत जैसे देशों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे की स्थितिको उजागर किया है।
 - समावेशी खाद्य प्रणालियों के लिये भी मजबूत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है। भारत को इन कार्यक्रमों का लंबा अनुभव है। भारत [राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम](#), [सार्वजनिक वितरण प्रणाली \(PDS\)](#), [एकीकृत बाल विकास योजना \(ICDS\)](#), [मध्याह्न भोजन कार्यक्रम](#) जैसे पोषण कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान कर गरीब और कमजोर समूहों की आय, आजीविका और पोषण में सुधार कर सकता है।
- **गैर-कृषि क्षेत्र:**
 - टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिये गैर-कृषि क्षेत्र की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। श्रम प्रधान वननिर्माण और सेवाएँ कृषि पर दबाव को कम कर सकती हैं क्योंकि कृषि से होने वाली आय छोटे भूमिधारकों और अनौपचारिक श्रमिकों हेतु पर्याप्त नहीं है।
 - इसलिये ग्रामीण [सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों \(MSME\)](#) और खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत करना समाधान का हिसा है।

आगे की राह

संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव ने सतत विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा के दृष्टिकोण को साकार करने और दुनिया में कृषि-खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव हेतु रणनीति विकसित करने के लिये पहले संयुक्त राष्ट्र [खाद्य प्रणाली](#) शिखर सम्मेलन के आयोजन का आह्वान किया है, जिससे सितंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा। यह [सतत विकास लक्ष्यों](#) (SDG) को प्राप्त करने के लिये नीतियों को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण चालक हैं। भारत को खाद्य प्रणाली परिवर्तन का भी लक्ष्य रखना चाहिये जो समावेशी और टिकाऊ हो, जिससे कृषि आय में वृद्धि तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस